

संपादकीय

श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा, बेहतर तालमेल के संकेत

श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुग्रह दिवसान्यके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान जो चुनूनर को संदेश देता था, वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नंदन मंत्री और अन्य नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप में रेखांकित हुआ। सबसे बड़ी और ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में नई दिल्ली को आश्वस्त किया कि वह श्रीलंका को जीमीन का इस्तेमाल भारत के हिंसों के खिलाफ नहीं होने देंगे। वह आश्वस्त इस मायने में अहम है कि श्रीलंका के हवनटोरा पोट में

श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा, बेहतर तालमेल के संकेत

बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और संपोर्ट करने वाले जीनी जहाजों का खड़ा होना भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। फिलातल जरूर श्रीलंका ने इन जहाजों के आने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक की समयसीमा अगले साल की सुरुआत में ही समाप्त होने वाली है। देखना होगा कि दिवसान्यके संस्करण भारत से किए अपने इस वादे को आगे किस तरह से पूरा करती है। खास बात यह कि

इस यात्रा में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के दीर्घकालिक नज़रियों की जारी रखी मिली। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने इस बात पर जो दिया कि भारत ने मुमोंबत के समय उनके देश की जिस तत्परता से बदल की वह महत्वपूर्ण है और वह बात है कि भारत की मदद जारी रहो। इस संदर्भ में यह क्या यात्रा की वह बात अभी हो जाती है। एक योग्य योग से दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी का एक दूसरे की दोनों नेताओं ने हिंद महासागर के लिए एक तालिका तभी मुद्रे पर भारत के पुराने रुख में दिखा लचीलापन

भी माना जा सकता है। भारत ने यह उमीद जल्द दोहराई कि श्रीलंका संविधान पर पूरी तरह अलग करते हुए प्रांगणियत काउंसिल के चुनाव कराएगा, लेकिन बयान में संविधान के 13वें संशोधन के जिक्र से बचा गया, जिसके मुताबिक तभी अलंकृत खंडों के तोकत देश की बात है। यह धेरेलू मोर्चे पर दिसानायके संस्करण के लिए रात की बात मानी जा रही है। दिसानायके आगे भीने जीनी की यात्रा पर जाने वाले हैं। जीनी कर्ज का जो बोझ आज भी श्रीलंका पर है, उसके मद्देनजर उन्हें जीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ही बढ़ावा होगा। देखने वाली बात यह होगा कि इस क्रम में वह भारत की जिताओं को किस तरह से और किस हृद तक प्राप्तिका में बनाए रखते हैं।

आज संसद में सांसदों का व्यवहार शर्म की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। पूरे देश की जनता ने बड़ा भरोसा जताते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा है, ताकि वे संसद के रूप में देश की भलाई के लिए नीति एवं नियम बनाएं, उसे लागू कराएं और जनजीवन को सुरक्षित तथा खुशहाल बनाते हुए। संसद की शपथ लेते समय सांसदगण इन सब बातों को ध्यान में रखने की कसम भी खाते हैं, लेकिन उनकी कसम बेबुनियाद ही होते हुए संसद की मर्यादाओं को आहत कर रही है। बीते कुछ समय से धरना-प्रदर्शन के साथ सड़क पर राजनीतिक दमखम दिखाने वाले नजारे संसद के दोनों सदनों में भी दिखने लगे हैं। भौतिक रूप से छीना-झपटी और हाथापाई की दिखती रही है और विचाराधीन विषय से दूर एक-दूसरे को हीन साबित करना ही उद्देश्य बन गया है। संसद का

ललित गर्ग

संविधान-निर्माता भीमारव अंबेडकर को लेकर भारतीय संसद में जो दूसरे पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, वे न केवल शर्मियार करने वाले हैं, बल्कि संसदीय गरिमा को धूंधलाने वाले हैं। अंबेडकर को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने सामाने हैं। दोनों पक्षों ने गुशवार को संसद परिसर में विरोध प्रश्नन किया। इस दैरान हाथापाई भी हुई जिसमें भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम विराला ने सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी को नियमों का पालन करना पड़ा।

संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय संसद के प्रांगण में जिस तरह की अशोभनीय एवं त्रासद स्थिति का उत्पन्न हुई है, वे हर लिहाज से दुखद, विडवनपूर्ण और निंदनीय है। अरोप-प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया है, मानो सत्ता पश्च और विषयक के बीच शुद्ध शून्या, द्वेष, नफरत की स्थितियां उगतर हो गई हैं। और तो और, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार जैसे आरोपों को लेकर पुलिस में मामला दर्ज होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुखद एवं अशालीन स्थितियों का उपचार न किया गया, तो संसद में काफी कुछ अप्रिय एवं अशोभनीय होने की आशकानी बलशाली होती।

कहना न होगा कि देश की संसद लोकतंत्र के वैचारिक सिखाया और धर्मांकित करने वाला शिखाया रखेंगे। इसके लिए इसकी गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों का माल कर्तव्य बन जाता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा होती है कि वे संसद की गरिमा को भंग न करें, अपना आचरण शुद्ध, शालीन एवं व्यवस्थित रखें और व्यथ को बयानाजी करना।

संसद की गरिमा का दांव पर लगना चिन्ताजनक



होता है कि पहली लोकसभा में हर साल 135 दिन बैठकें आयोजित हुई थीं। आज स्थिति कि तीनी नाजुक हो गई है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि पिछली लोकसभा में हर साल और सत्तान 55 दिन ही बैठकें आयोजित हुईं नयी लोकसभा की स्थिति तो और भी दुखद एवं दयनीय है। संसद में काम न होना, बार-बार संसदीय अवरोध होना तो एक संसद का व्यवहार शर्म की पराकार तक पहुंच गया है। पूरे देश की जनत ने बड़ा भरोसा जताता हुए अपनी प्रतिनिधियों को चुनाव लोकसभा में भेजा है, ताकि वे संसद के स्वतंत्रता एवं सत्यमें रखना। उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि वे संसद की गरिमा को भंग न करें, अपना आचरण शुद्ध, शालीन एवं व्यवस्थित रखें और व्यथ को बयानाजी करना।

जानकारी के साथ विषयक के नेता सरकारी पक्ष को अप्रोपत करने में जुट जाते हैं, बयानों तो डामरोड का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विषय लगातार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ दोहरा रहा है। वह सरकार को धेरने और अप्रोपत करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अवसर व्यवधान डालता है। लगता है कि विषय का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यालयी सुचारू रूप से न चल सके और सरकार को विफलता दर्ज हो। इस देश की जनत ने बड़ा नौबत पहुंचना ज्यादा चिन्ताजनक है। कोई भी दल से, किसी भी दल के सासद हो, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है।

सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि अगर संसद जोर आजमाइश एवं हिंसा का अखाड़ा और दलीलों का मंच है, यह किसी प्रकार को शारीरिक जोर-आजमाइश तक बढ़े नहीं जाने। यह काम नहीं होता कि अपनी जनत को धोना करना। उनकी जांच की जाए तो वह अपनी जनत को धोना करना। जानकारी के साथ विषयक के नेता सरकारी पक्ष को अप्रोपत करने में जुट जाते हैं, बयानों तो डामरोड का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विषय लगातार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ दोहरा रहा है। वह सरकार को धेरने और अप्रोपत करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अवसर व्यवधान डालता है। लगता है कि विषय का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यालयी सुचारू रूप से न चल सके और सरकार को विफलता दर्ज हो। इस देश की जनत ने बड़ा नौबत पहुंचना ज्यादा चिन्ताजनक है। कोई भी दल से, किसी भी दल के सासद हो, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है।

सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि

अगर संसद जोर आजमाइश एवं हिंसा का अखाड़ा नहीं है। अपनी जनत को धोना करना। जानकारी के साथ विषयक के नेता सरकारी पक्ष को अप्रोपत करने में जुट जाते हैं, बयानों तो डामरोड का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विषय लगातार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ दोहरा रहा है। वह सरकार को धेरने और अप्रोपत करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अवसर व्यवधान डालता है। लगता है कि विषय का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यालयी सुचारू रूप से न चल सके और सरकार को विफलता दर्ज हो। इस देश की जनत ने बड़ा नौबत पहुंचना ज्यादा चिन्ताजनक है। कोई भी दल से, किसी भी दल के सासद हो, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है।

जानकारी के साथ विषयक के नेता सरकारी पक्ष को अप्रोपत करने में जुट जाते हैं, बयानों तो डामरोड का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विषय लगातार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ दोहरा रहा है। वह सरकार को धेरने और अप्रोपत करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अवसर व्यवधान डालता है। लगता है कि विषय का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यालयी सुचारू रूप से न चल सके और सरकार को विफलता दर्ज हो। इस देश की जनत ने बड़ा नौबत पहुंचना ज्यादा चिन्ताजनक है। कोई भी दल से, किसी भी दल के सासद हो, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है।

जानकारी के साथ विषयक के नेता सरकारी पक्ष को अप्रोपत करने में जुट जाते हैं, बयानों तो डामरोड का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विषय लगातार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ दोहरा रहा है। वह सरकार को धेरने और अप्रोपत करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अवसर व्यवधान डालता है। लगता है कि विषय का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यालयी सुचारू रूप से न चल सके और सरकार को विफलता दर्ज हो। इस देश की जनत ने ब